(ग) डी० ए० आर के कार्यालय के एक अधिकारी के लेखा परीक्षा कार्यालय वाशिंगटन में तैनाती के आदेश किए जाने हैं। इन कार्यालयों के लिए कर्मचारियों का चयन लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के विभिन्न कार्यालयों से इच्छुक उम्मीदवारों में से किया जाता है। आवेदनों की जांच की जाती है तथा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा साक्षात्कार लेने के पश्चात् एक पैनल तैयार किया जाता है जिसमें से तैनातियां की जाती हैं।

वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सेवा विधि को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

2079. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है;

(ख) क्या सरकार उनके वर्तमान कार्यकाल के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी उनके कार्यकाल को बढ़ाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में श्री टी० एन० चतुर्वेदी की नियुक्ति की अवधि 26 मार्च, 1990 (अपराह्न) को समाप्त हो गई और उनका कार्यकाल बढ़ाने संबंधी कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विदेश दौरे

2080. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के वर्तमान नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने अपने वर्तमान पद की हैसियत से कितने विदेश दौरे किए तथा उन पर अब तक कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है;

(ख) उन्होंने किस-किस उद्देश्य से कौन-कौन से देशों की यात्रा की तथा प्रत्येक यात्रा पर अलग-अलग हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) भारत के वर्तमान नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने 27-3-1990 को ही कार्यभार ग्रहण किया है। भारत के पूर्व नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने सरकारी काम के संबंध में गत छः वर्षों के दौरान 13 अवसरों पर विदेशी दौरे किए। लगभग 8.64 लाख रुपए खर्च हुआ जिसमें 3.95 लाख रूपए की विदेशी मुद्रा सम्मिलित है।

(ख) ये यात्राएं, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रमंडल महालेखा परीक्षक सम्मेलन आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जिनके भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक सदस्य हैं, में भाग लेने के लिए की गयी थीं। इन यात्राओं का उपयोग भारतीय दूतावासों और अन्य संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए भी किया गया था। जिन देशों का

दौरा किया गया, उनके नाम तथा व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

उन देशों के नाम जिनका दौरा किया	अनुमानित व्यय		
	विदेशी मुद्रा (रुपयों में)	भारतीय रुपये	जोड़
जापान	11250	26104	37354
यू०के० और आस्ट्रिया . . .	22790	40157	62947
जापान, चीन और कोरिया . . .	25600	32079	57679
मलेशिया और सिंगापुर . . .	5660	6194	11854
यू.के., यू.एस.ए., पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस .	33822	26338	60160
यू.एस.ए., कनाडा, ब्राजील, पेरू और अर्जेण्टाइना .	30251	66950	97201
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड . . .	32000	56590	88590
थाइलैंड	11825	12310	24135
कनाडा, यू.के. और यू.एस.ए . . .	42769	50315	93084
फिलीपाइन्स और मलेशिया . . .	20436	21450	41886
इंडोनेशिया और सिंगापुर . . .	27565	19300	46865
यू.के., यू.एस.ए., पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन और नार्वे	42548	58851	101399
पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, फ्रांस, चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड, हंगरी, स्विटजरलैंड और यू.के.	88322	52655	140977
जोड़	394838	469293	864131

Effect of Smuggling of Watches on Watch Industry

2081. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that smuggling of watches has adversely affected the indigenous watch industry in the country; and

(b) if so, what steps Government propose to take to save the indigenous watch industry?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b) The value of seizure of watches anected during the calendar years 1986 to 1990 given in the table below show a declining trend. Available reports also indicate that the production of indigenous watches in the organised sector has increased from 7.7 million numbers in 1987 to about 9 million numbers (estamated) in 1989.

In 1985, the Government had announced a package of concessions to the Watch Industry including reduc-